भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3679
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना

3679. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में गत एक वर्ष के दौरान स्थापित किए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), उप-जिला अस्पताल और जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इनकी स्थापना के मानदण्ड क्या है और इन पर कितनी निधि व्यय की गई है;
(ग) राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने रोगियों का इलाज किया गया है और उस पर कितनी राशि व्यय की गई है; और
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी धनराशि तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकता है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। राजस्थान सहित देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप-जिला/मंडल अस्पतालों (एसडीएच), जिला अस्पतालों (डीएच) और मेडिकल कॉलेजों (एमसी) का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है।:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्थापना मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में) की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्र के लिए 15,000 से 20,000 की शहरी आबादी पर एक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 30,000 से 50,000 की शहरी आबादी पर एक शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू-पीएचसी), गैर-मेट्रो शहरों (5 लाख से अधिक आबादी) में प्रति 2.5 लाख की आबादी पर एक शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यू-सीएचसी) और मेट्रो शहरों में प्रति 5 लाख की आबादी पर एक यू-सीएचसी की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और फर्स्ट रेफरल यूनिट ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मध्यम परिचर्या सेवाएं प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान राज्य के लिए एनएचएम के तहत कुल 57,736.11 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों की उपलब्धता में अंतर को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में एम्स जोधपुर पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ग) और (घ): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1 सितंबर, 2019 से 28 फरवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (एमएए) योजना के तहत लगभग 108.70 लाख रोगियों का उपचार किया गया है, जिसका कुल मूल्य 12,036.03 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, राजस्थान में उक्त योजना के तहत फैमिली फ्लोटर आधार पर प्रति पॉलिसी वर्ष प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।

****